



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 151]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अप्रैल 8, 2005/चैत्र 18, 1927

No. 151]

NEW DELHI, FRIDAY, APRIL 8, 2005/CHAITRA 18, 1927

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 अप्रैल, 2005

सं. 32/2005-सीमाशुल्क

सा.का.नि. 222(अ).— केन्द्रीय सरकार, सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि ऐसा करना लोकहित में आवश्यक है, एतद्वारा ऐसे माल, जब इसे विदेश व्यापार नीति के पैराग्राफ 3.7 के अनुसार लक्ष्य + स्कीम के तहत जारी किए गए एक शुल्क क्रेडिट प्रमाणपत्र (जिसका इसके पश्चात् उक्त प्रमाणपत्र के रूप में उल्लेख किया गया है) के प्रति जब भारत में आयात किया जाए तो इसे निम्नलिखित से छूट प्राप्त होगी, -

(क) सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की पहली अनुसूची के अधीन उन पर उद्ग्रहणीय सम्पूर्ण सीमाशुल्क से ;

(ख) उक्त सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 3 के अधीन उन पर उद्ग्रहणीय सम्पूर्ण अतिरिक्त शुल्क से,-

निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहते हुए नामतः :-

(1) यह कि इस अधिसूचना के तहत लाभ केवल उक्त स्कीम के तहत किसी प्रमुख निर्यात गृह को जारी किए गए क्रेडिट प्रमाणपत्र के संबंध में वित्त वर्ष 2003-04 के दौरान किए निर्यातों की तुलना में वित्त वर्ष 2004-05 के दौरान किए गए निर्यातों के पोत-पर्यन्त निःशुल्क मूल्य में हुई उत्तरोत्तर वृद्धि के आधार पर उपलब्ध होगा ;

(2) यह कि उक्त प्रमाणपत्र लाइसेंसिंग प्राधिकारी द्वारा किसी प्रमुख निर्यात गृह को जारी किया गया हो और इसे माल पर उद्ग्रहणीय शुल्कों को डेबिट करने हेतु निकासी के समय उपयुक्त सीमाशुल्क प्राधिकारी के पास प्रस्तुत किया जाए, परन्तु इस छूट के लिए ;

बशर्ते कि शुल्क से छूट उस स्थिति में लागू नहीं होगी यदि माल पर उद्ग्रहणीय शुल्कों हेतु नामे खाते डालने के लिए उक्त प्रमाणपत्र में अपर्याप्त क्रेडिट उपलब्ध हो, परन्तु इस छूट के लिए ;

(3) यह कि उक्त प्रमाणपत्र और इसके तहत आयातित माल को न तो हस्तांतरित किया जाएगा और न ही बेचा जाएगा ;

बशर्ते कि जहां किसी ऐसे व्यापारिक निर्यातक द्वारा माल का आयात किया जाए जिसके पास कोई समर्थनकारी विनिर्माता जिसका नाम और पता उक्त प्रमाणपत्र पर निर्दिष्ट हो, उक्त माल का समर्थनकारी विनिर्माता द्वारा प्रयोग किया जा सकता है ।

(4) यह कि पूंजीगत माल कार्यालय उपकरण और व्यावसायिक उपकरण के संबंध में, क्षेत्राधिकारी उपायुक्त, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अथवा सहायक आयुक्त, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क जैसा भी मामला हो, के द्वारा एक प्रमाणपत्र प्रस्तुत किया जाता है जिसमें इस बात की पुष्टि की गई होती है कि पूंजीगत माल का अधिष्ठापन एवं प्रयोग आयातक की फैक्ट्री अथवा परिसरों में आयात की तिथि से छह महीने के भीतर अथवा बढ़ाई गई उस अवधि के भीतर किया गया हो जिसकी उपायुक्त, सीमाशुल्क अथवा सहायक आयुक्त, सीमाशुल्क द्वारा अनुमति दी जाए ।

बशर्ते कि ऐसी इकाइयां जो केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के पास पंजीकृत नहीं हों उनके संबंध में उक्त अधिष्ठापन प्रमाणपत्र किसी स्वतंत्र चार्टर्ड इंजीनियर द्वारा जारी किया जा सकता है ।

बशर्ते कि जहां पूंजीगत माल, कार्यालय उपकरण और व्यावसायिक उपकरण किसी ऐसे व्यापारी निर्यातक द्वारा आयात किए जाते हैं, जिनका कोई समर्थनकारी निर्माता हो/हों, तब इस माल को उक्त समर्थनकारी निर्माता/निर्माताओं के कारखाने अथवा परिसरों में अधिष्ठापित किया जा सकता है ।

(5) यह कि उक्त प्रमाणपत्र के तहत आयात मुम्बई, सिक्किम, कोलकाता, कोचीन, मगदल्ला, काकीनाड़ा, कांडला, मंगलौर, मारमागोवा, चैन्नई, नावांशेवा, पारादीप, पीपावव, सिक्का, तूतीकोरिन, विशाखापट्टनम, दाहेज, मुद्रा, नागापट्टिनम, ओखा, जामनगर और मुल्दवारका और पोरबन्दर स्थित समुद्री पत्तनों के माध्यम से अथवा अहमदाबाद, बंगलौर, भुवनेश्वर, मुम्बई, कोलकाता, कोयम्बटूर, दिल्ली, हैदराबाद, जयपुर, चैन्नई, श्रीनगर, त्रिवेन्द्रम, वाराणसी, नागपुर, कोचीन और राजासांसी (अमृतसर) स्थित किसी भी विमानपत्तन के माध्यम से अथवा आगरा, बंगलौर, कोयम्बटूर, दिल्ली, फरीदाबाद, गोवाहाटी, गुन्टूर, हैदराबाद, जयपुर, जालन्धर, कानपुर, लुधियाना, मुरादाबाद, नागपुर, पिम्परी (पुणे), पीतमपुर (इन्दौर), सूरत, तिरुपुर, वाराणसी, नासिक, रूद्रपुर (नैनीताल), दिघी (पुणे), बड़ोदरा, दौलताबाद (वंजारवाड़ी और मालीवाड़ा), वालुज (औरंगाबाद), अनापार्थी (आन्ध्र प्रदेश), सेलम, मालनपुर, सिंगनालुर, जोधपुर, कोटा, उदयपुर, अहमदाबाद, भिवाड़ी, मदुरई, भीलवाड़ा, पांडिचेरी, गड़ीहसालू, भटिण्डा, दम्पर (डेरा बासी), छेहराता (अमृतसर), करूर, मिराज, रिवाड़ी, भुसावल, जमशेदपुर, सूरजपुर और दादरी स्थित किसी अंतरदेशीय कंटेपर डिपो के माध्यम से या राणाघाट, सिंहबाद, रक्सौल, जोगबानी, नौतनवा (सौनोली), पैटरापोल और महादीपुर स्थित किसी भूमि सीमाशुल्क स्टेशनों के माध्यम से अथवा उक्त सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 76-क के तहत जारी की गई अधिसूचना में विनिर्दिष्ट विशेष आर्थिक जोनों से किया जाता है ।

(6) यह कि निर्माता प्रतिअदायगी उक्त सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 3 के तहत उद्ग्रहणीय अतिरिक्त शुल्क के सेनवेट का उक्त प्रमाणपत्र में क्रेडिट की गई राशि के प्रति प्रतिअदायगी लेने का हकदार होगा ।

2. निर्यातों की निम्नलिखित श्रेणियों को स्कीम के तहत निर्यात निष्पादन अथवा हक की संगणना हेतु नहीं गिना जाएगा :

- (i) विदेश व्यापार नीति के पैरा 2.35 के तहत शामिल किए गए आयातित माल का निर्यात अथवा जलयानों के माध्यम से किए गए निर्यात ।
- (ii) एसईजेड/ईओयू/ईएचटीपी/एसटीपी/बीटीपी स्कीमों के अंतर्गत कार्य करने वाली इकाइयों का निर्यात कारोबार अथवा उनके द्वारा उत्पादित माल जिसे डीटीए द्वारा निर्यात किया गया हो ।
- (iii) निर्यात समझे गए (जब भुगतान निर्बाध रूप से विदेशी मुद्रा में प्राप्त किया गया हो और भुगतान ईईएफसी लेखे से किया गया हो) ।
- (iv) निर्यात सेवा ।
- (v) अपरिष्कृत बिना कटे हुए और अर्ध पालिश हीरे और अन्य कीमती नगीनें ।
- (vi) किसी भी रूप में सोने, चांदी, प्लेटेनिम और अन्य कीमती धातुओं, जिनमें सादे और जड़े हुए आभूषण सम्मिलित हों ।
- (vii) किसी निर्यातक द्वारा किसी अन्य निर्यातक की ओर से किया गया निर्यात निष्पादन ।

3. लक्ष्य + स्कीम को बाद के वर्षों हेतु ऐसे संशोधनों के साथ जो आवश्यक हों, पुनः अधिसूचित किया जाए ।

स्पष्टीकरण : इस अधिसूचना में, -

- (i) “माल” का अर्थ किसी निविष्टि, पूंजीगत माल, कलपुर्जों सहित कार्यालय उपकरण, व्यावसायिक उपकरण, कार्यालय फर्नीचर और उक्त सीमाशुल्क टैरिफ अधिसूचना की पहली अनुसूची के अध्याय 1 से 24 में सूचीबद्ध किए गए कृषि उत्पाद जिन्हें महानिदेशक विदेश व्यापार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित किया जाए, जिन्हें विदेश व्यापार नीति के तहत निर्बाध रूप से आयात किया जा सकता है, -
- (ii) “ पूंजीगत माल” का अर्थ विदेश व्यापार नीति के पैराग्राफ 9.12 में निर्दिष्ट उसी अर्थ से है, -
- (iii) “विदेश व्यापार नीति” का अर्थ भारत सरकार के वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या 1/2004, तारीख 31 अगस्त, 2004 को प्रकाशित एवं समय-समय पर यथा-संशोधित विदेश व्यापार नीति 2004-2009 से अभिप्रेत है ;
- (iv) “लाइसेंसिंग प्राधिकारी” का अभिप्राय विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1992 (1992 का 22) की धारा 6 के तहत नियुक्त किए गए महानिदेशक, विदेश व्यापार अथवा उनके द्वारा उक्त अधिनियम के अधीन लाइसेंस देने के लिए प्राधिकृत किए गए किसी अधिकारी से है ।

[फा. सं. 605/50/2005-प्रतिअदायगी]

एच.के. प्रसाद, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE
(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 8th April, 2005

NO. 32/2005-CUSTOMS

G.S.R. 222(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby exempts goods when imported into India against a duty credit certificate issued under the Target Plus Scheme in accordance with paragraph 3.7 of the Foreign Trade Policy (hereinafter referred to as the said certificate) from, -

- (a) the whole of the duty of customs leviable thereon under the First Schedule to the Customs Tariff Act 1975 (51 of 1975); and
- (b) the whole of the additional duty leviable thereon under section 3 of the said Customs Tariff Act,-

subject to the following conditions, namely :-

- (1) that the benefit under this notification shall be available only in respect of duty credit certificate issued under the said Scheme to a Star Export House on the basis of incremental growth in FOB value of exports made during the financial year 2004-05 over the exports made during the financial year 2003-04;
- (2) that the said certificate has been issued to a Star Export House by the licensing authority and it is produced before the proper officer of customs at the time of clearance for debit of the duties leviable on the goods, but for this exemption:

Provided that exemption from duty shall not be admissible if there is insufficient credit in the said certificate for debiting the duties leviable on the goods, but for this exemption;

- (3) that the said certificate and goods imported against it shall not be transferred or sold:

Provided that where the goods are imported by a merchant exporter having supporting manufacturer(s) whose name and address is specified on the said certificate, the said goods may be utilised by the said supporting manufacturer(s);

- (4) that in respect of capital goods, office equipment and professional equipment, a certificate from jurisdictional Deputy Commissioner of Central Excise or Assistant Commissioner of Central Excise, as the case may be, is produced confirming installation and use of goods in the importer's factory or premises within six months from the date of import or within such extended period as the Deputy Commissioner of Customs or Assistant Commissioner of Customs may allow :

Provided that in respect of units which are not registered with the central excise, the said installation certificate may be issued by an independent Chartered Engineer;

Provided further that where the capital goods, office equipment and professional equipment, are imported by a merchant exporter having supporting manufacturer(s), the goods may be installed in the factory or premises of the said supporting manufacturer(s);

- (5) that the imports against the said certificate are undertaken through sea ports at Mumbai, Sikkim, Kolkata, Cochin, Magdalla, Kakinada, Kandla, Mangalore, Marmagoa, Chennai, Nhava Sheva, Paradeep, Pipavav, Sikka, Tuticorin, Visakhapatnam, Dahej, Mundhra, Nagapattinam,

Okha, Jamnagar, Muldwarka and Porbander or through any of the airports at Ahmedabad, Bangalore, Bhubaneswar, Mumbai, Kolkata, Coimbatore, Delhi, Hyderabad, Jaipur, Chennai, Srinagar, Trivandrum, Varanasi, Nagpur, Cochin and Rajasansi (Amritsar) or through any of the Inland Container Depots at Agra, Bangalore, Coimbatore, Delhi, Faridabad, Gauhati, Guntur, Hyderabad, Jaipur, Jalandhar, Kanpur, Ludhiana, Moradabad, Nagpur, Pimpri (Pune), Pitampur (Indore), Surat, Tirupur, Varanasi, Nasik, Rudrapur (Nainital), Dighi (Pune), Vadodara, Daulatabad (Wanjarwadi and Maliwada), Waluj (Aurangabad), Anaparthi (Andhra Pradesh), Salem, Malanpur, Singanalur, Jodhpur, Kota, Udaipur, Ahmedabad, Bhiwadi, Madurai, Bhilwara, Pondicherry, Garhi Harsaru, Bhatinda, Dappar (Dera Bassi), Chheharata (Amritsar), Karur, Miraj, Rewari, Bhusawal, Jamshedpur, Surajpur and Dadri or through the Land Customs Station at Ranaghat, Singhabad, Raxaul, Jogbani, Nautanva (Sonauli), Petrapole and Mahadipur or Special Economic Zones as specified in the notification issued under Section 76A of the said Customs Act;

- (6) that the importer shall be entitled to avail of the drawback or CENVAT credit of additional duty leviable under section 3 of the said Customs Tariff Act against the amount debited in the said certificate.

2. The following categories of exports shall not be counted for calculation of export performance or for computation of entitlement under the scheme -

- (i) export of imported goods covered under para 2.35 of the Foreign Trade Policy or exports made through transshipment;
- (ii) export turnover of units operating under SEZ/EOU/EHTP/STP/BTP Schemes or products manufactured by them and exported through DTA units;
- (iii) deemed exports (even when payments are received in Free Foreign Exchange and payment is made from EEFC account);
- (iv) service exports;
- (v) exports of rough, uncut and semi-polished diamonds and other precious stones;
- (vi) exports of gold, silver, platinum and other precious metals in any form, including plain and studded jewellery;
- (vii) Export performance made by one exporter on behalf of another exporter.

3. The Target Plus Scheme may be re-notified for subsequent years with such modifications as are necessary.

Explanation, - In this notification -

- (i) "goods" means any inputs, capital goods including spares, office equipment, professional equipment, office furniture, and agricultural products listed in Chapters 1 to 24 of the First Schedule to said Customs Tariff Act as may be notified by DGFT from time to time, which are freely importable under the Foreign Trade Policy;
- (ii) "capital goods" has the same meaning as assigned to it in paragraph 9.12 of the Foreign Trade Policy;
- (iii) "Foreign Trade Policy" means the Foreign Trade Policy 2004-2009, published by the Government of India in the Ministry of Commerce and Industry vide notification No.1/2004, dated the 31st August, 2004 as amended from time to time;
- (iv) "licensing authority" means the Director General of Foreign Trade appointed under section 6 of the Foreign Trade (Development and Regulation) Act, 1992 (22 of 1992) or an officer authorised by him to grant a license under the said Act.

[F. No. 605/50/2005-DBK]

H. K. PRASAD, Under Secy.

170 21/05-2